

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 11-10-2024

विषय सूची

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोर्टिफाइड चावल को जारी रखने को मंजूरी दी

21वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

दक्षिण पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा

मिडिल इनकम ट्रैप से निकलना

सिंथेटिक चिकित्सा छवियाँ (Synthetic Medical Images)

संक्षिप्त समाचार

ब्राह्मी शिलालेख

MLALAD निधि

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली

तटीय स्लैंग

एनाकोंडा रणनीति

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 150 वर्ष

साहित्य में नोबेल पुरस्कार

हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोर्टिफाइड चावल को जारी रखने को मंजूरी दी

सन्दर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनीमिया और पोषण संबंधी कमियों से निपटने के लिए कल्याणकारी योजनाओं में चावल को सुदृढ़ बनाने की पहल को 2028 तक बढ़ा दिया है।

पृष्ठभूमि

- देश में समावेशी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल को फोर्टिफाइड करना केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगा।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा, PM पोषण जैसे कार्यक्रमों के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
- FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में फूड फोर्टिफिकेशन संसाधन केंद्र (FFRC) की स्थापना की है।

फूड फोर्टिफिकेशन क्या है?

- WHO के अनुसार, फोर्टिफिकेशन किसी खाद्य पदार्थ या मसाले में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे, विटामिन और खनिज) की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाने की प्रथा है।
- ऐसा खाद्य पदार्थ की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है।

भारत में फूड फोर्टिफिकेशन

- चावल के फोर्टिफिकेशन में FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल की गुठली को नियमित चावल में शामिल करना सम्मिलित है।
- दूध को विटामिन A और D से फोर्टिफाइड किया जाता है, जो इन विटामिनों से जुड़ी कमियों से निपटने में सहायता करता है।
- आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए नमक को आयोडीन (आयोडीन युक्त नमक) से फोर्टिफाइड किया जाता है।

भारत में फोर्टिफिकेशन के लाभ

- **पोषण संबंधी कमियों को संबोधित करना:** भारत को छिपी हुई भूख से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ कैलोरी का सेवन पर्याप्त होने पर भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी उपस्थित है।
 - फोर्टिफिकेशन एनीमिया (आयरन), रिकेट्स (विटामिन डी) और अंधेपन (विटामिन ए) जैसी कमियों से निपटता है।
- **लागत प्रभावी:** फोर्टिफिकेशन लोगों को अपनी खाने की आदतों को परिवर्तित करने की आवश्यकता के बिना खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बेहतर बनाने का एक सस्ता तरीका है।

- **बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य:** एनीमिया, आयोडीन की कमी आदि जैसी स्थितियों को रोकने से फोर्टिफिकेशन से मातृ और शिशु मृत्यु दर के मामलों में बेहतर परिणाम मिलते हैं।
 - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में एनीमिया एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है, जो विभिन्न आयु समूहों और आयु स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करता है।
- कोपेनहेगन सर्वसम्मति का अनुमान है कि फोर्टिफिकेशन पर खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपये से अर्थव्यवस्था को 9 रुपये का लाभ होता है।

फूड फोर्टिफिकेशन की चिंताएँ

- **अवशोषण:** खाना पकाने के तरीकों और भोजन में अवरोधकों की उपस्थिति जैसे कारकों के कारण शरीर द्वारा जोड़े गए पोषक तत्व हमेशा पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते हैं।
 - **उदाहरण:** अनाज में फाइटेट्स जो आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हैं।
- **विनियामक निरीक्षण:** सख्त विनियामक निरीक्षण के बिना, अपर्याप्त या अत्यधिक फोर्टिफिकेशन का जोखिम होता है, जो स्वास्थ्य लाभ को कम कर सकता है।
- **सीमित पहुँच:** फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद समाज के सबसे गरीब तबके (कम क्रय शक्ति) तक पहुँचने में विफल रहते हैं, जो पोषण संबंधी कमियों से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग में से हैं।

सरकारी उपाय

- F+ लोगो फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को मानकीकृत करने और उन्हें दर्शाने के लिए FSSAI द्वारा की गई एक पहल है।
- दूध फोर्टिफिकेशन परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
- इस परियोजना का लक्ष्य दूध को विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड करना है।

आगे की राह

- फूड फोर्टिफिकेशन भारत की महत्वपूर्ण कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है।
- हालांकि यह कोई एकल उपाय नहीं है, लेकिन जब इसे अन्य पोषण रणनीतियों और मजबूत सरकारी समर्थन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और देश के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करने में सहायता कर सकता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI)

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक, 2006 के तहत स्थापित, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) मानव उपभोग के लिए भोजन की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित खाद्य-संबंधी मुद्दों को संभालता है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो खाद्य सुरक्षा के विभिन्न नियमों एवं पर्यवेक्षणों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

Source: TH

21वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने इस बात की समीक्षा की कि आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उन्होंने वियनतियाने, लाओ पीडीआर में भावी सहयोग की योजनाओं पर चर्चा की।

मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री योजना की घोषणा की, जिसमें शामिल हैं:
 - वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना,
 - एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक का जश्न मनाना,
 - 2025 तक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करना आदि।
- नेताओं ने घोषणा की कि वे डिजिटल समाधानों के माध्यम से आसियान और भारत में भुगतान प्रणालियों के बीच सीमा-पार संबंधों के सहयोग का पता लगाएंगे।
 - भारत, आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करने में अपने ज्ञान और अनुभवों को आसियान देशों के साथ साझा करेगा।
- नेताओं ने एक नई आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) बनाने पर सहमति व्यक्त की और दो संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया;
 - भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) के समर्थन से इंडो-पैसिफिक (AOIP) पर आसियान आउटलुक के संदर्भ में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य,
 - डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य।
- नेताओं ने संयुक्त गतिविधियों को समर्थन देने के लिए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत कोष के शुभारंभ का स्वागत किया।
 - भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत FTA (AITIGA) की समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITGA)

- भारत ने 2009 में आसियान के साथ वस्तुओं के क्षेत्र में FTA पर हस्ताक्षर किए थे, जो 2010 में लागू हुआ।
 - 2014 में सेवाओं के क्षेत्र में एक अलग FTA पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत और आसियान के बीच FTA को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITGA) के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते के परिणामस्वरूप आसियान को असंगत लाभ हुआ।

भारत के लिए आसियान का महत्व

- **चीन के प्रभाव का मुकाबला:** आसियान की रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है।

- **व्यापार और निवेश:** 2021-2022 में, भारत और आसियान के बीच व्यापार लगभग 110 बिलियन डॉलर था। आसियान देश भारतीय निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण गंतव्य हैं।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र:** आसियान भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है, जो क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है।
 - भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए आसियान को अपने केंद्र में रखती है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** भारत आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध और साइबर सुरक्षा पहलों पर आसियान के साथ सहयोग करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
- **कनेक्टिविटी और अवसंरचना:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी पहलों का उद्देश्य भारत और आसियान के बीच भौतिक संपर्क में सुधार करना, व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **आसियान के नेतृत्व वाली व्यवस्थाएँ:** भारत आसियान के नेतृत्व वाले प्रमुख मंचों का हिस्सा है,
 - जैसे कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS),
 - आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) और
 - आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus), जो रणनीतिक मुद्दों पर क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दक्षिण - पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)

- **परिचय:** यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य:** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- **इतिहास:** इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणापत्र) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी, जो आसियान के संस्थापक: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा किया गया था।
 - ब्रुनेई दारुस्सलाम 1984 में आसियान में शामिल हुआ, उसके बाद 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओ पीडीआर और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया शामिल हुए।
- **आसियान शिखर सम्मेलन:** यह आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार शामिल हैं। शिखर सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।
- पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था।

आगे की राह

- यह शिखर सम्मेलन आसियान-भारत संबंधों में एक माइलस्टोन साबित होगा, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए अपने सामरिक और आर्थिक महत्व की पुष्टि करेंगे।

- अपनी एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से आसियान के साथ भारत की सतत भागीदारी, आसियान के दृष्टिकोण और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित होकर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय वास्तुकला को आकार देना जारी रखेगी।

Source: PIB

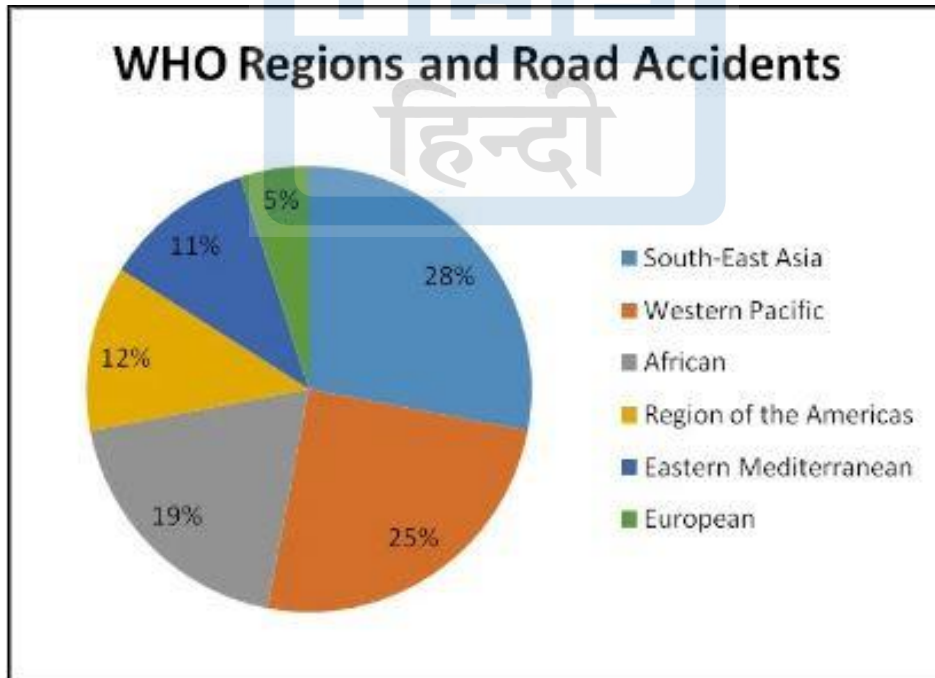
दक्षिण पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा

संदर्भ

- थाई स्कूल बस में हुई घातक आग दुर्घटना ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा के बारे में परिचर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।

दक्षिण पूर्व एशिया में सड़क दुर्घटनाएँ

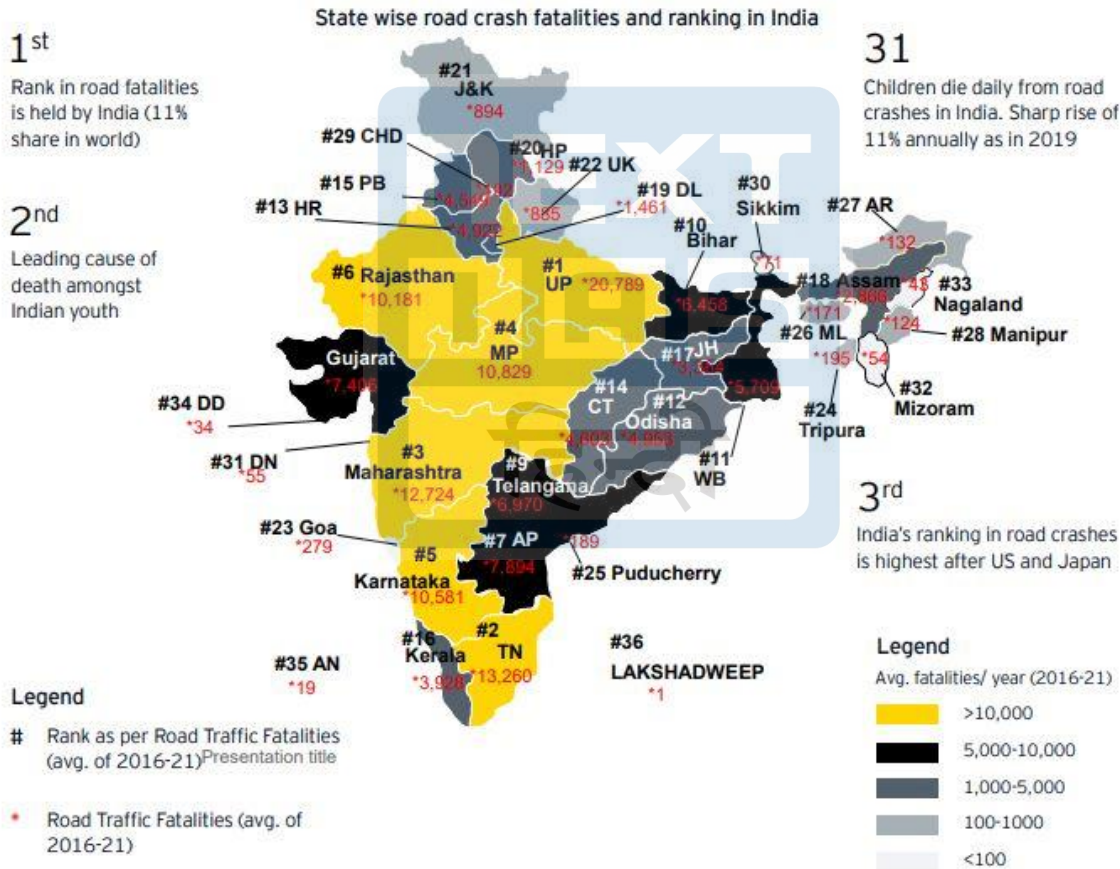
- इस क्षेत्र के 11 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।
- 2021 में अनुमानित 1.19 मिलियन वैश्विक सड़क यातायात मृत्युओं में से 3,30,223 दक्षिण पूर्व एशिया में हुई, जो वैश्विक भार का 28% है।
- दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रिपोर्ट की गई सभी सड़क यातायात मृत्युओं में पैदल यात्री, साइकिल चालक और दो या तीन पहिया वाहन सहित कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ता 66% हैं।



- **चुनौतियाँ:** मोटर चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों का उच्च प्रचलन, यातायात दुर्घटनाओं के अपर्याप्त आंकड़े, पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के लिए खराब बुनियादी ढांचा तथा सीमित आपातकालीन सेवाएँ।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 153,972 लोगों की मृत्यु हो गई।
- यह प्रति 100,000 जनसंख्या पर 11.3 मृत्यु के समान है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मृत्युओं में 11% हिस्सेदारी के साथ, भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- डेटा बताता है कि भारत में 90% घटनाओं में यातायात उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का कारण है। इनमें से 70% मामलों में तेज गति से वाहन चलाने की वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं।
- पिछले दशक (2009-2019) में सड़क यातायात दुर्घटनाएँ भारत में स्वास्थ्य भार में 13वीं सबसे बड़ी योगदानकर्ता रही हैं।



क्या आप जानते हैं?

- सितंबर 2020 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021-2030 शुरू किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मृत्युओं और चोटों को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करना है।
- सड़क सुरक्षा पर दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया, जिसने 2011-2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का पहला दशक घोषित किया।

- ब्रासीलिया घोषणा में, भाग लेने वाले देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य निर्धारित किए और अगले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का संकल्प लिया।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भारत, 2010:** इसमें बेहतर सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों के सख्त प्रवर्तन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, जन जागरूकता अभियान और दुर्घटना के बाद बेहतर देखभाल की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय समिति (SCCoRS):** इस मुद्दे को संबोधित करने, देश में दुर्घटना से होने वाली मृत्युओं को कम करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए 2014 में इसकी स्थापना की गई थी।
- **भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए:** भारत उन शुरुआती 100+ देशों में से एक था, जिन्होंने 2015 में ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी, अर्थात् 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्युओं और चोटों की संख्या को आधा करना।
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:** इस अधिनियम ने यातायात उल्लंघनों के लिए उच्च दंड का प्रावधान किया, जिसमें तेज गति से गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना और हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना शामिल है।
 - इसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सख्त प्रावधान पेश किए और किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सख्त दंड लगाया।
- SCCoRS के निर्देशों के तहत पूरे भारत में ई-प्रवर्तन एकरूपता पर कार्य करने के लिए 2023 में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
 - यह प्रभावी ई-प्रवर्तन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट के कार्यान्वयन के लिए एक अवधारणा योजना तैयार करेगी।

आगे की राह

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से पता चलता है कि जिन देशों ने पद्धतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है, वे मृत्यु दर में 50% कमी लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या इसे प्राप्त करने के करीब हैं।
- ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जैसे देश संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.6 से आगे निकल गए हैं और इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है। इसलिए, भारत इन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकता है।
- भारत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर पर्याप्त शोध किया है।
- सरकार नीतियों और कार्य योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए इन संस्थानों के साथ सहयोग कर सकती है।

- शोधकर्ता ऐसे मॉडल विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं जो सरकार को विभिन्न सड़क खंडों के लिए अनुकूलित त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अनुसंधान को वित्तपोषित करके, जागरूकता फैलाकर, ड्राइवरो के लिए सख्त स्वास्थ्य नीतियां बनाकर या आराम करने के लिए सड़क के किनारे बुनियादी ढांचा प्रदान करके सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है।

Source: IE

मिडिल इनकम ट्रेप से निकलना

समाचार में

- विश्व विकास रिपोर्ट 2024 "मिडिल इनकम ट्रेप, या आय में वृद्धि के बावजूद विकास दर में मंदी की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

क्या आप जानते हैं?

- "मिडिल इनकम ट्रेप" एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहाँ देश उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- 2007 में इंदरमीत गिल और होमी खरास द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा, निम्न से मध्यम आय स्तर पर संक्रमण करने वाले देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा लिखी गई है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि जब अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पहुंचती हैं, जो अमेरिका के 11% के बराबर है, तो प्रति व्यक्ति आय में ठहराव आ जाता है, जिससे उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है।
- इसमें उन देशों के विकास अनुभवों के आधार पर इस जाल से बाहर निकलने के लिए आवश्यक नीतियों और रणनीतियों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने संक्रमण को प्रबंधित किया।

प्रमुख निष्कर्ष

- वैश्विक निर्यात वृद्धि धीमी हो गई है, और कई देश संरक्षणवाद का सामना कर रहे हैं।
- समय से पहले विऔद्योगीकरण विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे विकास में इसकी भूमिका कम हो रही है।
- पिछले 34 वर्षों में, केवल 34 मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्थाएँ - जिन्हें प्रति व्यक्ति आय \$1,136 और \$13,845 के बीच की अर्थव्यवस्थाएँ माना जाता है - उच्च आय स्तरों पर पहुँची हैं।
- कई सफल देश यूरोपीय संघ का हिस्सा थे, जो मुक्त पूंजी और श्रम गतिशीलता से लाभान्वित हुए।
- दक्षिण कोरिया और चिली जैसे सफल मामले राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका को दर्शाते हैं।
 - दक्षिण कोरिया की सरकार ने निजी क्षेत्र की गतिविधियों को निर्यात-संचालित विकास मॉडल की ओर निर्देशित किया, सफल कंपनियों को समर्थन देकर पुरस्कृत किया जबकि कम प्रदर्शन करने वालों को विफल होने दिया।
 - इसी तरह, चिली के लक्षित हस्तक्षेपों ने इसके प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों को मजबूत किया।

भारत के लिए आर्थिक चुनौतियाँ

- **भारत में परिदृश्य:** राज्य के करीबी अरबपतियों के प्रभाव ने घरेलू पूंजी निवेश में बाधा उत्पन्न की है।
 - महामारी के बाद विनिर्माण में ठहराव और कृषि में कम उत्पादक रोजगारों की ओर वापसी।
 - वास्तविक GDP वृद्धि मजदूरी वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो रही है, जिससे उपभोग मांग कम हो रही है।
 - महंगाई के मुकाबले नाममात्र मजदूरी वृद्धि पिछड़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वास्तविक मजदूरी वृद्धि हुई है।
 - PLFS के अनुसार, अप्रैल और जून 2023-24 के बीच अखिल भारतीय स्तर पर नियमित वेतन श्रमिकों के लिए नाममात्र मजदूरी केवल 5% के आसपास बढ़ी है, और आकस्मिक श्रमिकों के लिए लगभग 7% बढ़ी है।
 - आर्थिक विकास में श्रमिकों की अपर्याप्त भागीदारी से मध्यम आय के जाल के बने रहने का खतरा बना रहता है।

सुझाव

- हालिया रिपोर्ट में "3i" दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है: निवेश, अन्तः प्रवाह और नवाचार।
- अर्थव्यवस्थाओं को निवेश करना चाहिए, नई वैश्विक प्रौद्योगिकियों का समावेश सुनिश्चित करना चाहिए और घरेलू नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करना चाहिए।
- यह कोई आसान कार्य नहीं है और इसके लिए सक्रिय और उत्तरदायी राज्य नीति की आवश्यकता है।
- आधुनिक अर्थव्यवस्था में, कई ऐसी बाधाएं हैं, जिन्हें भारत को मध्यम आय के जाल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के लिए दूर करना होगा।
- शक्तिशाली व्यावसायिक संस्थाएं निवेश और नवाचार के माध्यम से विकास को गति दे सकती हैं।
- दक्षिण कोरिया और चिली के ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि सत्तावादी शासन तेजी से विकास हासिल कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर।
 - इसलिए भारत के लिए मध्यम आय के जाल से बाहर निकलने के लिए प्रभावी राज्य हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

Source: TH

सिंथेटिक चिकित्सा छवियाँ (Synthetic Medical Images)

समाचार में

- AI-जनित सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का विकास हुआ है।

सिंथेटिक मेडिकल छवियों के बारे में

- वे MRI, सीटी स्कैन या एक्स-रे जैसे पारंपरिक इमेजिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए बिना AI या कंप्यूटर एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न होते हैं।

- ये चित्र पूरी तरह से गणितीय मॉडल या AI तकनीकों जैसे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GANs), डिफ्यूजन मॉडल और ऑटोएनकोडर का उपयोग करके बनाए जाते हैं।
 - GANs में एक जनरेटर होता है जो छवियाँ बनाता है और एक विभेदक जो उनकी प्रामाणिकता का आकलन करता है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सुधार करता है।
 - VAEs छवियों को अव्यक्त स्थानों में संपीड़ित करता है और उनका पुनर्निर्माण करता है। प्रसार मॉडल यादृच्छिक शोर को चरण-दर-चरण यथार्थवादी छवियों में बदल देता है।

लाभ:

- यह इंटर- और इंटर-मोडैलिटी ट्रांसलेशन की अनुमति देता है, जिससे उपलब्ध डेटा से गुम स्कैन तैयार करने में सहायता मिलती है।
 - **इंट्रामोडैलिटी ट्रांसलेशन:** एक ही इमेजिंग मोडैलिटी के अंदर सिंथेटिक इमेज तैयार करता है (उदाहरण के लिए, MRI स्कैन का पुनर्निर्माण)।
 - **इंटर-मोडैलिटी ट्रांसलेशन:** विभिन्न मोडैलिटी के बीच डेटा को परिवर्तित करके सिंथेटिक इमेज तैयार करता है (उदाहरण के लिए, MRI डेटा से सीटी स्कैन तैयार करना)।
- यह वास्तविक रोगी डेटा के बिना तैयार किया जाता है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ कम होती हैं और डेटा साझा करने में सुविधा होती है।
- यह वास्तविक चिकित्सा छवियों को इकट्ठा करने से जुड़े समय और खर्च को संबोधित करता है।

चुनौतियाँ:

- डीपफेक बनाने का जोखिम, जो रोगियों का प्रतिरूपण कर सकता है, जिससे गलत निदान और धोखाधड़ी वाले दावे हो सकते हैं।
- सिंथेटिक छवियाँ वास्तविक दुनिया के चिकित्सा डेटा की सूक्ष्म बारीकियों को नहीं पकड़ पातीं, जिससे AI निदान की सटीकता खतरे में पड़ जाती है।
- सिंथेटिक छवियों पर अत्यधिक निर्भरता वास्तविकता और बनावट के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से ऐसे नैदानिक मॉडल तैयार हो सकते हैं जो वास्तविक रोगी मामलों के एकरूप नहीं होते हैं।

उपाय:

- जबकि सिंथेटिक मेडिकल इमेज नवाचार के अवसर प्रदान करती हैं, उन पर निर्भरता विनियामक और नैतिक चुनौतियों का सामना करती है। स्वास्थ्य सेवा निर्णयों की अखंडता को बनाए रखने के लिए मानवीय निगरानी महत्वपूर्ण है।
- सिंथेटिक छवियों की गुणवत्ता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तविक दुनिया की चिकित्सा जटिलताओं को दर्शाती हैं, चिकित्सकों और AI इंजीनियरों के बीच सहयोग आवश्यक है।
- वास्तविक दुनिया की स्वास्थ्य सेवा समझ को कम किए बिना लाभ को अधिकतम करने के लिए सिंथेटिक छवियों के उपयोग को आशावाद और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

Source:TH

संक्षिप्त समाचार

ब्राह्मी शिलालेख

समाचार में

- आंध्र प्रदेश के अमरावती मंडल के धरणीकोटा गांव में दूसरी शताब्दी ई. का एक ब्राह्मी शिलालेख मिला है।
 - स्मारक स्तंभ पर उत्कीर्ण यह शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।

About Brahmi Inscription

- ब्राह्मी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसका इतिहास मौर्य काल से जुड़ा है।
- प्रारंभिक ब्राह्मी शिलालेख सामान्यतः प्राचीन भाषा प्राकृत में लिखे गए थे, हालाँकि बाद के शिलालेख संस्कृत में लिखे गए थे।
 - यह देवनागरी, तमिल, बंगाली, कन्नड़ और अन्य सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों का अग्रदूत है।
- ब्राह्मी शिलालेख भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
- ब्राह्मी ने पूरे दक्षिण एशिया और उससे आगे, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध ग्रंथों और शिलालेखों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Source: TH

MLALAD फंड

समाचार में

- दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा चुनावों से पहले परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) निधि को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹15 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

MLALAD फंड के बारे में

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) निधि विधान सभा के सदस्यों (MLA) को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने की अनुमति देती है।
- **उद्देश्य:** ये निधि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है।
 - ये निधि स्थानीय विकास जैसे सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पार्कों के विकास और कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने के लिए विधायकों को जारी की जाती है।

- **प्रक्रिया:** प्रत्येक विधायक के पास अपने जिले के उपायुक्त को सुझाव देने का विकल्प होता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र द्वारा वर्ष-दर-वर्ष दिए जाने वाले आवंटन की सीमा तक क्या कार्य करवाए।
- MLALAD योजना के तहत प्रदान की गई राशि जिलों या स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए अनुदान सहायता के रूप में जारी की जाती है।
- MLALAD निधि से व्यय न की गई राशि समाप्त नहीं होती है और अगले वित्तीय वर्ष में विधायक को आवंटित कर दी जाती है।

Source: TH

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(NCBC)

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) महाराष्ट्र की कुछ जातियों/समुदायों को OBCs की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- इसे शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 द्वारा गठित किया गया था और अब तक आयोग को 2016 तक 7 बार पुनर्गठित किया जा चुका है।
- वर्तमान आयोग (8वें) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसे "संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018" के माध्यम से गठित किया गया है।
 - अनुच्छेद 338B डाला गया है, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा।
 - इसमें भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने और उचित सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है।

Source: PIB

जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जलवायु संबंधी खंडित आंकड़ों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक-जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (RB-CRIS) का प्रस्ताव दिया है, जो वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम उत्पन्न करता है।

रिज़र्व बैंक – जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (RB-CRIS)

- यह दो भागों में होगा, ताकि जलवायु से संबंधित डेटा में अंतर को समाप्त किया जा सके जो वर्तमान में खंडित रूप में उपलब्ध है।
 - **भाग एक:** एक वेब-आधारित निर्देशिका जो RBI की वेबसाइट पर मौसम संबंधी और भू-स्थानिक डेटा सहित विभिन्न सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध करेगी।
 - **भाग दो:** मानकीकृत डेटासेट वाला एक डेटा पोर्टल, जो चरणबद्ध तरीके से केवल विनियमित संस्थाओं के लिए सुलभ होगा।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं को उनकी बैलेंस शीट और समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए जलवायु जोखिम आकलन करने में सहायता करना है।
 - प्रभावी जोखिम आकलन के लिए स्थानीय जलवायु परिदृश्यों, पूर्वानुमानों और उत्सर्जन पर उच्च गुणवत्ता वाला डेटा आवश्यक है।

Source: TH

तटीय स्लैग

सन्दर्भ

- शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन में तटीय स्लैग जमा से निर्मित एक नई तरह की अवसादी चट्टान का दस्तावेजीकरण किया है।

परिचय

- स्लैग कृत्रिम जमीन का एक प्रमुख घटक है।
- यह धातु ऑक्साइड एवं सिलिकॉन डाइऑक्साइड युक्त एक मिश्रित सामग्री है, और यह लोहा तथा इस्पात उद्योगों में इस्पात बनाने की प्रक्रिया का एक उप-उत्पाद है।
- यह चट्टान परमाणु हथियार परीक्षणों के कचरे में पिघले हुए कांच और स्टील जैसी अन्य संरचनाओं तथा समुद्र में तैरते प्लास्टिक के टुकड़ों के बाद बनती है, जिन्हें रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया ने पकड़ लिया है।
- लिथिफिकेशन प्रक्रिया स्लैग सहित औद्योगिक कचरे को तलछटी चट्टानों में कठोर बनाती है, जिससे कृत्रिम जमीन बनती है।
- जब ये तलछटी चट्टानें समय के साथ खराब होती हैं, तो वे पर्यावरण में तलछट छोड़ती हैं। चूंकि चट्टानें औद्योगिक कचरे से भरी होती हैं, इसलिए उनके तलछट में प्रायः जहरीली धातुएँ होती हैं जो मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करती हैं।

Source: TH

एनाकोंडा रणनीति

सन्दर्भ

- ताइवान के नौसेना कमांडर ने हाल ही में दावा किया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वीप राष्ट्र पर दबाव बनाने के लिए 'एनाकोंडा रणनीति' का उपयोग कर रही है।

एनाकोंडा रणनीति क्या है?

- यह एक सैन्य रणनीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य दुश्मन के संसाधनों को धीरे-धीरे घेरना और काटना है, जिससे सीधे टकराव के बिना उन्हें प्रभावी रूप से "निचोड़" कर अधीनता में लाया जा सके।
- यह रणनीति अमेरिकी गृहयुद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
 - इस रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक और सैन्य रूप से संघ का दम घोटना था, ठीक उसी तरह जैसे एनाकोंडा सांप अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मारकर उसे मार डालता है।
- ताइवान के विरुद्ध चीन की 'एनाकोंडा रणनीति' में कथित तौर पर सैन्य युद्धाभ्यास, मनोवैज्ञानिक रणनीति और साइबर युद्ध का मिश्रण शामिल है, जो अंततः ताइवान की सुरक्षा को कमजोर करता है।

Source: The Economist

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 150 वर्ष

सन्दर्भ

- वर्ष 2024, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा।

परिचय

- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और डाक क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्राथमिक मंच है।
- उत्पत्ति:** 9 अक्टूबर 1874 को, 22 देशों ने बर्न की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे जनरल पोस्टल यूनियन का निर्माण हुआ।
 - बाद में इसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के नाम से जाना जाने लगा।
- सदस्य देश:** UPU के 192 सदस्य देश हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश UPU का सदस्य बन सकता है।
 - संयुक्त राष्ट्र का कोई भी गैर-सदस्य देश UPU का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसके अनुरोध को UPU के कम से कम दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा स्वीकृति दी जाए।
- मुख्यालय:** स्विट्स राजधानी बर्न
- 4 निकायों से मिलकर बनता है;**
 - कांग्रेस:** यह सर्वोच्च प्राधिकरण है; प्रत्येक चार वर्ष में इसकी बैठक होती है।

- **प्रशासन परिषद:** यह इसकी गतिविधियों की निगरानी करती है और विनियामक, प्रशासनिक, विधायी और कानूनी मुद्दों का अध्ययन करती है।
- **डाक संचालन परिषद:** यह UPU का तकनीकी और परिचालन विचार है और इसमें 48 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें कांग्रेस के दौरान चुना जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो:** यह रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

विश्व डाक दिवस

- विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है।
- इसकी घोषणा सबसे पहले 1969 में टोक्यो में UPU कांग्रेस में की गई थी, ताकि वैश्विक स्तर पर डाक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके।
- **2024 का थीम:** विभिन्न देशों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष।

Source: UPU

साहित्य में नोबेल पुरस्कार

समाचार में

- साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके "ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को प्रकट करने वाले गहन काव्यात्मक गद्य" के लिए दिया गया है।
 - साथ ही, उनके सफल उपन्यास, द वेजिटेरियन (2007), जिसका 2015 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ने 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में इसकी स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग नोबेल पुरस्कारों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। नोबेल को डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था।
- पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम, स्वीडन में होता है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए, जो ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है।
- नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित छह श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:
 - शांति
 - भौतिकी
 - रसायन विज्ञान
 - चिकित्सा (फिजियोलॉजी)
 - साहित्य
 - आर्थिक विज्ञान: इसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जोड़ा था।

- 1974 के बाद से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिये जा सकते, उन मामलों को छोड़कर जहां पुरस्कार की घोषणा के बाद प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है।

Source: TH

हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab)

सन्दर्भ

- चिकित्सा उद्योग में हॉर्सशू क्रैब की मांग है।

हॉर्सशू क्रैब के बारे में

- हॉर्सशू क्रैब लिमुलिडे परिवार के समुद्री और खारे पानी के आर्थ्रोपोड हैं और ऑर्डर ज़िफ़ोसुरा के एकमात्र जीवित सदस्य हैं।
- वे 300 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद हैं, जिससे वे डायनासोर से भी पुराने हो गए हैं।



- **आवास:** अंडे देर से वसंत और गर्मियों में तटीय समुद्र तटों पर रखे जाते हैं। अंडे सेने के बाद, किशोर हॉर्सशू क्रैब ज्वारीय समतल के रेतीले समुद्री तल पर तट से दूर पाए जा सकते हैं।
- वयस्क हॉर्सशू क्रैब समुद्र में गहराई तक भोजन करते हैं जब तक कि वे अंडे देने के लिए समुद्र तट पर वापस नहीं आ जाते।
 - हॉर्सशू केकड़ों की अधिकतम संख्या ओडिशा तट पर पाई जाती है और बालासोर सबसे बड़ा स्पॉनिंग ग्राउंड हुआ करता था।
- **खतरे:** भोजन, चारा एवं बायोमेडिकल परीक्षण के लिए अत्यधिक कटाई, और तटीय पुनर्ग्रहण तथा विकास से आवास की हानि के कारण।
- **औषधीय उपयोग:** हॉर्सशू क्रैब के चमकीले नीले रक्त का उपयोग टीकों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खतरनाक जीवाणु विषाक्त पदार्थों से दूषित नहीं हैं।
 - उनके रक्त में एक विशेष थक्का बनाने वाला एजेंट लिमुलस एमेबोसाइट लाइसेट होता है जो एंडोटॉक्सिन नामक एक संदूषक का पता लगाता है।

- प्रत्येक वर्ष, दवा कंपनियां पांच लाख अटलांटिक हॉर्सशू क्रैब को एकत्रित करती हैं, उनका खून निकालती हैं और उन्हें वापस समुद्र में छोड़ देती हैं, जिसके बाद उनमें से कई मर जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** अमेरिकी हॉर्सशू क्रैब को विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और ट्राई-स्पाइन हॉर्सशू क्रैब को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटर्ड स्पीशीज में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - हॉर्सशू केकड़े भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध हैं।

Source: TH

